

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:—92/16 ((RCMS No.2016/00097) 18 आयुध अधिनियम 1959)

रामनाथ पुत्र बालमुकुन्द जाति गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर

.....रैसपोडैन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर दिनांक 05.07.2016

उपरिस्थिति:—

1. श्री भगवत सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

निर्णय दिनांक: 08.11.2017

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 20/2000 दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.15 को पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में अवगत कराया कि आवेदन के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 41/04 धारा 216ए ता0हि0 थाना सदर में दर्ज हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। इसलिये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। अपीलान्ट को धारा 17(3) का नोटिस जारी किया जिसका अपीलान्ट ने जबाबपेश किया कि प्रार्थी को दोष मुक्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण आपसी रंजिश में दर्ज कराया था। प्रार्थी एक सीधा साधा कृषक व्यक्ति है उक्त आर्म्स अपनी व अपने परिवार की निजी सुरक्षा हेतु ले रखा है। इसका उसने कभी कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने थाने में दर्ज अभियोग में तथ्यों को छिपाया गया है। अपीलान्ट के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरुपयोग होने की संभावना

को देखते हुए तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के अपीलान्त के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने तथा शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिनांक 05.07.16 को पारित किये। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त के विरुद्ध मु0 नं0 294/05 एफआईआर सं0 41/04 पुलिस थाना सदर धौलपुर में हुए आदेश के आधार पर अपीलान्त का आर्म्स लाइसेंस निरस्त किया है। उसमें अपीलान्त को दिनांक 01.07.2015 को बरी किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई है। उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है। इसलिये उक्त निर्णय की आड़ में अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त के लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि अपीलान्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा किसी थाने में विचाराधीन नहीं है और न ही कोई आरोप लाइसेंस का दुरुपयोग करने के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है, जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्त के विरुद्ध मु0 नं0 41/04 धारा 216 ता0 हि0 थाना सदर धौलपुर में दर्ज हुआ था जिसमें अपीलान्त द्वारा भगौडों (फरार व्यक्तियों) को शरण देना अंकित किया है। अपीलान्त आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है तथा अपीलान्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ है। इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सिफारिश के आधार पर लोक सुरक्षा एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्त को आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त का अनुज्ञापत्र संख्या 20/2000 दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत था। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.15 को पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 41/04 धारा 216ए ता0 हि0 थाना सदर में प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा भगौडों को शरण देना अंकित किया है तथा अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। अपीलान्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण धारा 216ए भा0द0 सं0 में संदेह का लाभ देकर अपीलान्त को दोष मुक्त किया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण के लिये अनुशंसा नहीं की है। लोकशान्ति व

लोकसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील-अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official